

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ प्र

पत्रांक सं०-20/संघर्ष

दिनांक 05.01.2019

सेवा में,

अध्यक्ष,

उ.प्र.पा.का.लि./उ.प्र.रा.वि.उ.नि.लि./उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि./उ.प्र.ज.वि.नि.लि.,
शक्ति भवन, लखनऊ।

महोदय,

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ प्र के दिनांक 27.11.2018 को दिये गये प्रस्ताव/नोटिस का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें दिनांक 08 एवं 09 जनवरी 2019 को भारत सरकार के श्रम विरोधी निजीकरण इत्यादि के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया है परन्तु विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मात्र कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में आपको अवगत कराया जा चुका है। भारत सरकार इलेक्ट्रीसिटी अमेण्डमेन्ट बिल 2018 संसद में लाने जा रही है जिससे बिजली विभाग में वितरण का निजीकरण कर दिया जायेगा। उपभोक्ताओं पर भी अनायास बोझ बढ़ेगा। इस संदर्भ में नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रीसिटी इम्प्लॉई एण्ड इंजीनियर्स(एन सी सी ओ ई ई ई) ने निर्णय लिया है कि निम्न समस्याओं का समाधान यदि सरकार नहीं करती है तो दिनांक 08 एवं 09 जनवरी 2019 को परियोजना एवं ट्रांसमिशन की पाली 400केवी एवं उससे ऊपर की पाली को छोड़ कर समस्त इंजीनियर एवं कर्मचारी 02 दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे।

मुख्य मांग :-

- बिजली निगमों का एकीकरण कर उप्र राज्य विद्युत परिषद लि० का पुनर्गठन किया जाये, इलेक्ट्रीसिटी (अमेण्डमेन्ट) बिल 2018 वापस लिया जाये, आगरा फ्रेन्चाईजी व ग्रेटर नोएडा का निजीकरण निरस्त किया जाये।
- वर्ष 2000 के बाद भर्ती हुए सभी कार्मिकों के लिए पुरानी पेन्शन प्रणाली लागू की जाये।
- बिजली कर्मियों की वेतन विसंगतियों का द्विपक्षीय वार्ता द्वारा तत्काल निराकरण किया जाये।
- समस्त रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाये और नियमित प्रकृति के कार्यों में संविदा/ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर तेलंगाना सरकार की तरह संविदा कर्मियों को नियमित किया जाये।
- सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों का नवीनीकरण किया जाये और निजी घरानों से मंहगी बिजली खरीद हेतु सरकारी बिजली घरों को बन्द करने की नीति समाप्त की जाये।

महोदय बिजली विभाग एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसकी वजह से हड़ताल न करके परियोजना एवं ट्रांसमिशन की पाली 400केवी एवं उससे ऊपर के सबस्टेशनों को छोड़ कर सभी कर्मचारी अभियन्ता 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि कार्य बहिष्कार के बीच किसी भी अभियन्ता कर्मचारी का उत्पीड़न हुआ तो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति सीधी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगी।

सादर,

भवदीय

शैलेन्द्र दुबे

शैलेन्द्र दुबे
संयोजक

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति

राजीव सिंह
राजीव सिंह
महासचिव

उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ

गिरीश पाण्डेय
महामंत्री

विद्युत मजदूर पंचायत, उप्र

महेन्द्र राय
मुख्य महामंत्री
उप्र बिजली कर्मचारी संघ

राजपाल सिंह
अध्यक्ष
हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्प.यू.उप्र

सुहैल आबिद
महामंत्री
उप्र बिजली मजदूर संगठन

राजेन्द्र प्रसाद घिल्लियाल
प्रदेश अध्यक्ष
उप्र विद्युत मजदूर संघ,
भा मा सा

शम्भू रतन दीक्षित
अध्यक्ष
उप्र ताप विद्युत मजदूर संघ
भा मा सा

परशुराम
महासचिव
रा.वि.प.प्रा. कर्मचारी संघ, उप्र

पी एस बाजपेयी
अध्यक्ष
उप्र रा.वि.प. श्रमिक संघ

विशम्भर सिंह
महामंत्री
उप्र बिजली बोर्ड इम्प. यू.

राम सहारे वर्मा
प्रान्तीय महामंत्री
विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ

पूसेलाल
अध्यक्ष
विद्युत मजदूर यूनियन उप्र

जी.पी. सिंह
महामंत्री
विद्युत पैरामेडिकल एसोसिएशन

प्रतिलिपि प्रतिष्ठा में :-

1. मा. मुख्यमंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
2. मा. ऊर्जा मंत्री, उप्र सरकार, लखनऊ।
3. मुख्य सचिव, उप्र शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उप्र सरकार, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उप्र पावर कारपोरेशन लि/उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि/उप्र जल विद्युत निगम लि/उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

शैलेन्द्र दुबे
संयोजक